



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—४, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 22 अप्रैल, 2025

बैशाख 2, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (गोपन) अनुभाग—५

संख्या B.S.- 87 / 2025-सी०एक्स०-५

लखनऊ, 22 अप्रैल, 2025

अधिसूचना

प०आ०—७५

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं० का०आ०—१११४(अ), दिनांक 11 मार्च, 2025 द्वारा विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जम्मू एण्ड कश्मीर इतेहादुल मुस्लिमीन (जेकेआईएम) को “विधि विरुद्ध संगठन” घोषित किया गया है। यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पाँच वर्ष के लिए लागू होगी।

2—उक्त के साथ ही अधिसूचना सं० का०आ० 1114 (अ), दिनांक 11 मार्च, 2025 के आलोक में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं० का०आ०—१३६६(अ), दिनांक 24 मार्च, 2025 द्वारा पूर्वोक्त विधि विरुद्ध संगठन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 42 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 7 एवं 8 के अन्तर्गत प्रयोग की जानी वाली सभी शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा किया जाना प्राधिकृत किया गया है।

3—उक्त के साथ ही गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 14017/4/2025-NI-MFO दिनांक 25 मार्च, 2025 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा संसूचित किया गया है कि राज्य सरकार लिखित में आदेश द्वारा निर्देश

दे सकेगी कि कोई शक्ति जो उसके द्वारा प्रयोग के लिए निर्देशित है, ऐसी परिस्थितियों और शर्तों के अन्तर्गत जैसा कि निर्देश में विविर्दिष्ट हो, यथा स्थिति राज्य सरकार के किसी अधीनस्थ व्यक्ति द्वारा भी प्रयोग की जायेगी।

भारत सरकार के उक्त आदेश संख्या 14017/4/2025-NI-MFO दिनांक 25 मार्च, 2025 द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार के अन्तर्गत समस्त पुलिस आयुक्तों तथा जिला मजिस्ट्रेट्स द्वारा किया जायेगा।

अतः इस सम्बन्ध में एतद्वारा समस्त पुलिस आयुक्तों तथा जिला मजिस्ट्रेट्स को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का तदनुसार प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

आज्ञा से,
डा० संजीव गुप्ता,
सचिव।

संख्या B.S.- 87 / 2025-सी०एक्स०-५, दिनांक 22 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 14017-4-2025-NI-MFO दिनांक 25 मार्च, 2025 की प्रति संलग्नकों सहित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित :-

- (1) श्री अभिजीत सिन्हा, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
- (2) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (3) समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
- (5) अपर पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक ए०टी०एस०, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- (6) गृह पुलिस अनुभाग-१/३/४/११/१२/१४
- (7) गार्ड फाइल-गृह गोपन अनुभाग-५।

संलग्नक—यथोपरि।

आज्ञा से,
वी०के० सिंह,
विशेष सचिव।

No. 14017/4/2025-NI-MFO
भारत सरकार / Government of India
गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi
Dated the 25th March, 2025

ORDER

Subject: Declaring Jammu and Kashmir Ittihadul Muslimeen (JKIM) as an unlawful association under section 3 (1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 Notification issued by the Central Government under section 42, directing that all powers which may be exercised by the Central Government under section 7 and section 8, shall be exercised also by any State Government/ Union Territory Administrations.

WHEREAS, the Central Government, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), has declared Jammu and Kashmir Ittihadul Muslimeen (JKIM) as an 'unlawful association' *vide* notification number S.O. 1114(E) dated the 11th March, 2025;

AND, WHEREAS, in exercise of the powers conferred by section 42 of the said Act, the Central Government has directed *vide* Notification S.O. 1366 (E) dated 24th March, 2025, that all the State Governments and Union Territory administrations shall also exercise the powers exercisable by the Central Government under section 7 and section 8 of the said Act;

AND, WHEREAS, it has been considered necessary that the powers directed to be exercised by all the State Governments and Union Territory administrations as above, may be exercised by any person subordinate to the State Governments and Union territory administrations.

NOW, THEREFORE, the approval of the Central Government under section 42 of the said Act is hereby conveyed that the State Governments and Union Territory Administrations may, by order in writing, direct that any power which has been directed to be exercised by it, shall, in such circumstances and under such conditions, as may be specified in the direction, be exercised by any person subordinate to the State Government or the Union Territory administrations, as the case may be.

By order,
ABHIJIT SINHA,
Joint Secretary to the Government of India.
Phone: 011-23093124.